सिविल विविध

माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन के समक्ष

राम कुमार आदि,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य आदि,-प्रतिवादी

सिविट रिट संख्या 1859, 1971

17 अगस्त 1971

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV) - धारा 3 - औद्योगिक विवाद पंजाब) नियम (1958) - नियम 57 - धारा 3 के तहत गठित कार्य समिति - नियम 57 के तहत ऐसी समिति को भंग करने की शक्ति - चाहे वह यूएएसी-न्यायिक प्रकृति की हो - विघटन से पहले सुनवाई का अवसर-जबकि समिति के सदस्यों को दिया जाना है।

निर्णय लिया गया कि औद्योगिक विवाद (पंजाब) नियम, 1958 के नियम 57 के तहत यह आवश्यक नहीं है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत गठित वर्क्स कमेटी के निर्वाचित सदस्यों को इसके खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर दिया जाए। इसका विघटन, लेकिन यह अपने आप में यह मानने के लिए पर्याप्त है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ नियम के तहत आदेश पारित किया जाना है, उन्हें नोटिस जारी करना और सुनना आवश्यक नहीं है। जहां मालिक को किसी ऐसे मामले का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी सौंपा गया है जिसके परिणाम से किसी व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप शक्ति का प्रयोग करने के लिए उस प्राधिकारी पर एक कर्तव्य लगाया गया है। न्याय। नियम 57 के तहत एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां अर्ध-औषधीय प्रकृति की हैं। इसलिए, यह उचित प्राधिकारी पर निर्भर है कि वह प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करे और इस नियम के तहत आगे बढ़ने से पहले कार्य समिति के सदस्यों को एक अवसर देना चाहिए। यदि यह अवसर दिया जाता है, तो सदस्य उपयुक्त प्राधिकारी को यह समझाने की स्थिति में हो सकते हैं कि समिति को भंग करने का आदेश देने के लिए इस नियम में उल्लिखित कोई भी शर्त मौजूद नहीं है।

(पैरा 6),

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि सरकार-प्रतिवादी संख्या 1-नंबर के आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, परमादेश या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए। हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14 अप्रैल, 1971 (अनुलग्नक 'डी') में प्रकाशित आईडी/डब्ल्यूसी/1-10898 और आगे प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय में रिट याचिका का अंतिम निपटान लंबित

होने तक, संचालन और विवादित आदेश (अनुलग्नक 'डी') के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता विधिवत निर्वाचित कार्य समिति के सदस्य के रूप में अभी भी पद पर हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ए.एस. आनंद।

एम. एल. सरपाल, प्रतिवादी संख्या 3 के वकील।

प्रतिवादी की ओर से डी.एस. लांबा उप महाधिवक्ता (हरियाणा)।

जैन, जे.-

(1) राम कुमार और दो अन्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हरियाणा में प्रकाशित प्रतिवादी नंबर 1 के आदेश को रद्द करने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए यह याचिका दायर की है। सरकारी राजपत्र (असाधारण), दिनांक 14 अप्रैल, 1971 (याचिका के अनुलग्नक 'डी' की प्रतिलिपि बनाएँ)।

(2) इस मामले के तथ्य इस प्रकार बताए जा सकते हैं:-

याचिकाकर्ता मेसर्स हिसार टेक्सटाइल मिल्स, हिसार (इसके बाद टेक्सटाइल मिल्स के रूप में संदर्भित) के कर्मचारी हैं। याचिकाकर्ता नंबर 1, हिसार टेक्सटाइल मजदूर सभा का अध्यक्ष है, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 3, हिसार टेक्सटाइल मिल्स वर्कर्स यूनियन का सदस्य है। हरियाणा सरकार द्वारा कपड़ा मिलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार कार्य समिति गठित करने की आवश्यकता थी। 1947 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) और उसके तहत बनाए गए नियम। वर्क्स कमेटी का चुनाव कैसे हुआ, इसकी जानकारी देने के बाद याचिका में कहा गया है कि सेवा राम सहित याचिकाकर्ता 1 से 3 तक। कंवर सैन. बगरू मल और बीरबल शर्मा को कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य समिति के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित किया गया। आगे कहा गया है कि कपड़ा मिलों के प्रबंधक, प्रतिवादी नंबर 3 ने औद्योगिक विवाद (पंजाब) नियम, 1958 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 39 के अनुसार कार्य समिति के सात सदस्यों को नामित किया।). तदनुसार 14 सदस्यों वाली एक कार्य समिति का गठन किया गया और इसके सदस्यों में से, याचिकाकर्ता संख्या 3 को कार्य समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार गठित कार्य समिति 14 अप्रैल, 1971 तक नियमों के अनुसार ठीक से काम करती रही, जब याचिकाकर्ताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब विवादित आदेश जारी किया गया और हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया, जिसमें कहा गया था कि कार्य समिति को नियमों के नियम 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर भंग कर दिया गया था (याचिका के अनुलग्नक 'डी' की प्रतिलिपि बनाएँ)। यह वह अधिसूचना है जिसकी वैधता को इस याचिका के माध्यम से विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है।"

(3) प्रतिवादी संख्या 3, हिसार टेक्सटाइल मिल्स के प्रबंधक, विमल कृष्ण खन्ना द्वारा एक हलफनामे के माध्यम से लिखित बयान दायर किया गया है।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील डॉ. आनंद ने तर्क दिया कि जिस आदेश के द्वारा टेक्सटाइल मिल्स की वर्क्स कमेटी को भंग कर दिया गया था, वह अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता था। विद्वान वकील के अनुसार, विवादित आदेश कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं को सुने बिना पारित किया गया था और यह एक ऐसी जांच पर आधारित था जिसके साथ याचिकाकर्ता कभी भी जुड़े नहीं थे। यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एम. एल. सरपाल ने स्वीकार किया कि विवादित आदेश कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता है; हालाँकि, चूँकि मेरे सामने प्रस्तुत प्रश्न में एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु शामिल था, इसलिए मैंने स्वतंत्र रूप से इसकी सत्यता का निर्णय करने का निर्णय लिया।

(5) पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद। मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों में काफी दम है। जिन तथ्यों पर मेरे सामने कोई विवाद नहीं था, उनसे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को विवादित आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और न ही वे उस जांच से जुड़े थे जिसके आधार पर विवादित आदेश पारित किया गया था। वे कार्य समिति को नियमों के नियम 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर भंग कर दिया गया था, जो निम्नानुसार है: -

57. कार्य समिति का विघटन.

राज्य सरकार, या जहां धारा 3 के तहत शक्ति धारा 39 के तहत किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंपी गई है, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा कर सकते हैं। ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह उचित समझे, किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा किसी भी कार्य समिति को भंग कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि समिति का गठन इन नियमों के अनुसार नहीं किया गया है या नहीं श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या में से दो-तिहाई से भी कम, बिना किसी उचित कारण के समिति की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहे हैं या समिति ने, किसी अन्य कारण से, कार्य करना बंद कर दिया है: बशर्ते कि जहां इस नियम के तहत एक कार्य समिति को भंग कर दिया जाता है, नियोक्ता, और यदि आवश्यक हो, तो ऐसा कर सकता है राज्य सरकार या. जैसा भी मामला हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अनुसार समिति का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।" विघटन की शक्ति का प्रयोग उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नियम में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है, जैसे (i) समिति का गठन नियमों के अनुसार नहीं किया गया है या (ii) जो दो तिहाई से कम नहीं हो। श्रमिकों के कई प्रतिनिधि बिना किसी उचित कारण के समिति की बैठक में भाग लेने में विफल रहे हैं या (ii) समिति ने किसी अन्य कारण से काम करना बंद कर दिया है। यह पता लगाने के लिए कि क्या विघटन की कोई शर्त मौजूद है, उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसी जांच करने की शक्ति दी गई है जो वह उचित समझे। नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति सीमित है और इसका प्रयोग उसमें निर्दिष्ट मामलों के बाहर नहीं किया जा सकता है। सत्ता का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। यदि कार्य समिति के सदस्यों को अवसर दिया जाता है, तो वे उपयुक्त प्राधिकारी को यह समझाने की स्थिति में हो सकते हैं कि कोई भी शर्त मौजूद नहीं है। इसके अलावा वे ऐसी परिस्थितियाँ सामने ला सकते हैं

जो उपयुक्त प्राधिकारी को कार्य समिति को भंग करने जैसा कठोर कदम न उठाने के लिए मना सकें। एक कार्य समिति को भंग करना, जो निर्वाचित सदस्यों से भी गठित होती है, एक बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि यह निर्वाचित सदस्यों को कार्य समिति में बने रहने के उनके अधिकार से वंचित करता है।

(6) यह सच है कि बदले में नियम की आवश्यकता नहीं है कि वर्क्स कमेटी के निर्वाचित सदस्यों को वर्क्स कमेटी के विघटन के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा यह मान लें कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध उस नियम के तहत आदेश पारित किया जाना है, उन्हें नोटिस जारी करना और सुनना आवश्यक नहीं है। जहां किसी मामले को निर्धारित करने के लिए उचित प्राधिकारी को शक्ति प्रदान की जाती है, जिसके परिणाम से किसी व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप शक्ति का प्रयोग करने के लिए उस प्राधिकारी पर एक कर्तव्य लगाया गया है। न्याय। ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि लाला श्री भगवान और अन्य बनाम राम चंद और अन्य (ए.आई.आर.. 1965 एस.सी. 1767,) मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा देखा गया था, शक्ति की प्रकृति अनिवार्य रूप से यह सीमा लगाएगी कि शक्ति का प्रयोग अनुरूपता में किया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ. मामले के इस दृष्टिकोण से, एकमात्र निष्कर्ष जिस पर पहुंचना मेरे लिए संभव है, वह है शक्तियां नियमों के नियम 57 के तहत एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियम अर्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं और उस नियम के तहत आगे बढ़ने से पहले प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना उचित प्राधिकारी पर निर्भर है और उसे कार्य समिति के सदस्यों को एक अवसर देना चाहिए। ताकि उनके खिलाफ जो मामला कायम किया जा सके, उसका निपटारा किया जा सके। चूंकि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं को यह अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वर्क्स कमेटी का विघटन अमान्य और शून्य था। मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे पीरजादे हुसैन सब मोहदीन बनाम श्रम आयुक्त, बैंगलोर और अन्य, (१९६४ (११) एल.एल.जे. ५६१) में मैसूर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले से पूर्ण समर्थन मिलता है, जहां बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पर यह इस प्रकार देखा गया था: -

"फिर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की पहली दलील से निपटने पर कि कार्य समिति में उनके चुनाव को रद्द करने से पहले उनके मुवक्किल को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 1 की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। ऐसा नहीं है विवाद है कि इस मामले में याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से तय है कि किसी व्यक्ति को सुने बिना उसे प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को कार्य समिति के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं जिससे उसे उचित सूचना दिए बिना वंचित नहीं किया जा सकता।"

(7) किसी अन्य बिंदु पर आग्रह नहीं किया गया।

(8) ऊपर दर्ज कारणों से मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और 14 अप्रैल, 1971 के आक्षेपित आदेश को रद्द करता हूं (याचिका के अनुलग्नक 'डी' की प्रतिलिपि बनाएँ)। चूँकि उत्तरदाताओं की ओर से याचिका का विरोध नहीं किया गया था, इसलिए मैं लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देता।

*****

<u>अस्वीकरण</u>: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा